डा. मुरली मनोहर जोशी : सभापति महोदय, असम में जब कभी जन शिक्षा संस्थाओं को बढ़ायेंगे तो मजूली आईलैंड के बारे में हम जरूर साहनुभूति से विचार करेंगे। यह द्वीप ऐसा है इसके बारे में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मैं इससे सहमत हूं। लेकिन जो दूसरे प्रस्ताव आये थे, वे इससे थोड़ा बेहतर थे। हमारी सहानुभूति इसके साथ है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा

685. **श्रीमती सविता शारदा :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा से निपटने के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों को विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ अनुबंध करने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) भारतीय विश्वविद्यालयों को सक्षम प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापन सम्पन्न करने की अनुमति प्रदान की गई है । केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के मामले में सक्षम प्राधिकरण मानव संसाधन मंत्रालय है और राज्य विश्वविद्यालयों तथा सम विश्वविद्यालयों के मामले में सक्षम प्रधिकरण क्रमशः राज्य सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है।

Competition in the field of higher education

†*685. SHRIMATI SAVTTA SHARDA : WiU the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under consideration of Government for allowing Indian Universities to sign contract with foreign universities to deal with the increasing competition in the field of higher education;

(b) if so, the details thereof; and

(c) by when the final decision is likely to be taken in this regard?

TOE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) to (c) Indian Universities are permitted to enter into

† Original notice of the question was received in Hindi.

Memorandum of Understanding with the foreign universities with prior approval of the competent authority. In the case of Central Universities, the competent authority is the Ministry of Human Resource Development and in case of State and Deemed Universities, it is the State Government and University Grants Commission respectively.

श्रीमती सविता शारदा : धन्यवाद सभापति। आज देश को स्वतंत्र हुए 50 वर्ष से ज्यादा हो गये हैं ।

श्री सभापति : आप भूमिका मत बनाइये । आप सीधे प्रश्न करिए। सबको मालूम है कि देश के आजाद हुए कितने वर्ष हो गये हैं।

श्रीमती सविता शारदाः सर,ठीक है। मैं सीधे प्रश्न करती हूं । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि क्या भारतीय विश्वविद्यालयों का विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ अनुबंध केवल केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को ही दिया जायेगा या अन्य विश्वविद्यालयों को भी दिया जायेगा? मैं यह भी जानना चाहती हूं कि इसके परिणाम स्वरूप-------।

श्री सभापति : मंत्री जी, आप बताइये ।

श्रीमती सविता शारदा : सर, यह इसी से संबंधित प्रश्न है।

श्री सभापति : ये दो सवाल हो गये हैं।

डा. मुरली मनोहर जोशी : सभापति महोदय, मैंने प्रश्न के उत्तर में ही लिखा है कि राज्य विश्वविद्यालयों के मामले में सक्षम प्राधिकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। इनसे अनुमति मिल सकती है।

श्रीमती सविता शारदाः सभापति महोदय, इस समय भारत में आकर उच्चस्तर की शिक्षा प्राप्त करने वाले विदेशी छात्रों की संख्या कितनी है ? अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त करने वाले विदेशी छात्रों की संख्या कितनी है ? अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवता की शिक्षा हमारे देश में उपलब्ध होने के परिणाम स्वरूप भारत में अपेक्षाकृत कम कीमत पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विदेशी छात्रों की संख्या में कितनी वृद्धि होने की संभावना है? मंत्री महोदय से मैं यह भी जानना चाहती हूं कि -------।

श्री सभापति : आप तीन-चार सवाल नहीं करेंगी । एक क्वेश्चन का सप्लीमेंट्री पूछने का यह मतलब नहीं है कि आप दस सवाल कर लें।

डा. मुरली मनोहर जोशी : सभापति महोदय, पूरी संख्या जानने के लिए तो इन्हें अलग से नोटिस देना पड़ेगा। यह इस सवाल से उत्पन्न प्रश्न नहीं है । यह तो केवल अनुमति का सवाल है।

श्री जनेश्वर मिश्र : धन्यवाद सभापति महोदय, । मैं सीधे सवाल करूंगा। मंत्री जी ने जवाब दिया है कि भारतीय उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों की मानसिक प्रतिस्पर्धा के लिए विदेश के विश्वविद्यालयों से अनुबंध करने की इजाजत दे दी गई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में भारतीय विश्वविद्यालय दुनिया के विश्वविद्यालयों से कमजोर हो गये हैं, इसके क्या कारण है ? दुनिया में कितने विश्वविद्यालय हैं जहां उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिभा जिसको अंग्रेजी में एक्सीलेंस कहते हैं, उसको विकसित करने के लिए मातृभाषाओं के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है, किसी विदेशी भाषा का इस्तेमाल नहीं होता है। विदेशी भाषा का जहां-जहां इस्तेमाल होता है वहां प्रतिभा कुंठित होती है। क्या मंत्री जी इसके बारे में जानते हैं ?

श्री सभापति : यह तो आपके स्वभाव के अनुसार प्रश्न है।

डा. मुरली मनोहर जोशी : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है वह इस प्रश्न से मेल नहीं खाता है क्योंकि मैंने कहीं भी प्रतिस्पर्धा के ------।

श्री सभापति : मैंने कहा है कि स्वभाव के अनुसार है, प्रश्न के अनुसार नहीं है।

डा. मुरली मनोहर जोशी : सभापति महोदय, मैंने इसमें यह नहीं कहा है कि प्रतिस्पर्धा के कारण हम ऐसा करेंगे। यह बिल्कुल नहीं कहा है । हमने इसमें केवल इतनी बात कही है कि भारतीय विश्वविद्यालयों को विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ अनुबंध करने की, एमओयु साइन करने की इजाजत है। यह बराबरी के स्तर पर है। हमने यह कभी नहीं कहा है कि हमारे विश्वविद्यालय उनसे कम हैं। ...(**व्यवधान**) ...

श्री जनेश्वर मिश्र : उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा हो। मंत्री जी जवाब देते हों या न देते हों। ... (**व्यवधान**) ...

डा. मुरली मनोहर जोशी : उसका जो प्रश्न है। मैं आपके माध्यम से सम्माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे इस प्रश्न को पढ़ लें। प्रश्न का हैडिंग तो न प्रश्नकर्ता लगाता है, न मैं लगाता हूं । वह तो आपका कार्यालय लगाता है । लेकिन जो प्रश्न किया गया है मैं उसका उत्तर दूंगा। हमने कभी ऐसा नहीं कहा है कि प्रतिस्पर्धा के कारण हम ऐसा कर रहे हैं या हम प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गये हैं। बल्कि हमने यह कहा है कि हम बराबरी के आधार पर उनके साथ एमओयूज करेंगे। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से, जहां से हमारा सीधा संबंध है उनको हम बराबर बताते हैं कि एक तरफा नहीं होगा। अगर उनके अध्यापक यहां आएंगे। तो हमारे भी वहां जाएंगे, हमारे छात्र वहां जाएंगे तो उनके भी यहां वहां आएंगे। इसलिए उनका सवाल नहीं है । मैं यहां यह बता दूं कि हमारे देश में कोई भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय ऐसा नहीं-है एक दो जो नए खुले है, उनको छोड़कर-जो विश्व में प्रतिस्पर्धा में किसी से भी पीछे हो। बल्कि विश्व के अनेक विश्वविद्यालय उनके साथ अनुबंध करने के लिए बराबर यहां अप्लाई करते रहते हैं, हमारे यहां आवेदन करते रहते हैं

उसका सवाल नहीं है। दूसरा सवाल जो उन्होंने किया, उसमें सारे विश्व के विश्वविद्यालय की जानकारी तो आज मेरे पास नहीं है । जब माननीय सदस्य इस बारे में जानकारी पाने के लिए नोटिस देंगे तो वह जानकारी भी हम इकट्ठी करेंगे। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि अधिकांश स्थानों पर शिक्षण उसी राज्य की मातृभाषा में ही होता है। यह बात सच है । यह बात भी सच है कि जहां आप प्रशिक्षण मातृभाषा के अतिरिक्त दूसरी भाषा के द्वारा करवाते हैं, वहां छात्रों के मानस पर बोझ पड़ता है ।

Support prices of agricultural products

†686. SHRISUKHDEV SINGHUBRA:

Dr.ABRARAHMED†:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government propose to authorize the State Governments to fix the minimum support price of agricultural products which do not get the expected price and the loss suffered would be shared by the State Governments and the Central Government; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTEROFAGRiaJLTURE(SHRI AJIT SINGH): (a) No, Sir. (b) Does not arise.

डा. अबरार अहमद : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि कृषि उत्पाद की लागत बराबर बढ़ रही है , चाहे खाद का मूल्य हो, बीज का हो, डीजल का हो, बिजली की कीमत हो लेकिन किसानों को जो सब्सिडी और रियायत दी जा रही है, वह बराबर घट रही है। इस परिस्थिति में जो किसान की हालत बनी है, कहीं भुखमरी है तो कहीं आत्महत्याएं हो रही है, माननीय मंत्री जी इन बढ़ती हुई उत्पादन लागतों के संदर्भ में किसान को उचित मूल्य दिलवाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं?

श्री अजित सिंह : माननीय सभापति महोदय, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के लिए एक कमीशन है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और बाकी सब फैक्टर्स को भी ध्यान में रखता है, जब वह दाम तय करता है । सरकार जब दाम तय करती है तो उसमें सीएसीपी की रिकमेंडेशंस तथा स्टेट की रिकमेंडेशंस इन सब पर विचार करके ही दाम तय किए जाते हैं।

डा. अबरार अहमद : महोदय माननीय मंत्री जी ने कमीशन की बात कही, वह तो हम सबको मालूम है लेकिन जैसा मैंने कहा कि उत्पादन लागत बढ़ रही है किन्तु उसकी तुलना में

† The question was actually asked on the floor of House by Dr. Abrar Ahmed.